in the current financial year for Andaman and Lakshadweep Harbours. The following works are under execution:—

(i) Construction of dry dock in Port Blair;

(ii) Construction of New Jetties in 10 Islands;

(iii) Slipway at Port Blair;

(iv) Office and residential building at Port Blair.

(v) Construction of Hards.

(vi) Ancillary and foreshore facilities (Stage I) excluding Little Andaman.

(vii) Breakwater at Little Andaman.

(viii) Ancillary and foreshore facilities (Stage I) for Little Andaman.

(ix) Bunkering facilities at Little Andaman.

(x) Ancillary and foreshore (Stage II) for Little Andaman.

रियायती आल रूट डी० टी० सी० बस पास

596. श्री केशव राव पारधी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के एल० एल० बी० और अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को रियायती आल रूट डी० टी० सी० बस पास की सुविधा मिलती है;

(ख) यदि हां, तो इंस्टीट्यूट आफ कोस्ट एंड वर्क्स एकाउन्ट्स के उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह सुविधा न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार उन विद्यार्थियों को भी यह सुविधा देने का विचार कर रही है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां,

(ख) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण (मुफ्त और रियायती पास) अधिनियम 1954 के अधीन दिल्ली परिवहन निगम द्वारा रियायती पास जारी किए जाते हैं । इस अधिनियम के तहत दिल्ली में स्थिति शिक्षा संस्थाओं के वास्तविक विद्यार्थियों को शिक्षा निदेशालय दिल्ली या उपकुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय की सिफारिश पर और केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे यह उसके नियंत्रण में चल रहे प्रशिक्षण और निर्माण केन्द्रों और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली और आयुर्वेदिक व यूनानी का तिब्बिया कालेज, दिल्ली के वास्तविक विद्यार्थियों को, सरकार या दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अगंहीन वास्तविक विद्यार्थियों को और चार्टर्ड एकाउन्टेंसी का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उन निदिष्ट लिपिकों को रियायती पास दिए जाते है जिन्हें चार्टर्ट एकाउन्टेंट की फर्म से जिसके तहत वे काम करते हैं न तो कोई छात्रवृत्ति और न ही कोई वेतन मिलता है ।

इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट्स एंड वर्क्स एकाउन्टैण्टस की नार्दन इंडिया रीजनल कौंसिल से दिल्ली परिवहन निगम के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं कि यह सुविधा उसके विद्यार्थियों को भी दी जाये । इन आवेदन पत्रों की निगम द्वारा जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि

यह कौंसिल अन्य उन शिक्षण संस्थाओं की तरह है जो व्यापारिक रीति से विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयार कराती है और यह कौंसिल उक्त प्राधिकरणों में से किसी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है । इसलिए इस कौंसिल के विद्यार्थियों को रियायती पास देना स्वीकार्य नहीं है ।

(ग) नहीं, ऊपर प्रश्न के भाग (ख) में कारण दे दिए गए हैं ।

Recognition to Kampuchea

597. DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names of countries that have recognised the Government of Heng Samrin in Kampuchea before India did;

(b) the names of countries that recognised the same Government after India accorded the recognition; and

(c) any policy—inference that the Government draws from these statistics?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) On the basis of the information now available with the Government, the following countries had recognised the People's Republic of Kampuchea before India recognised that Government:

Laos, Vietnam, Soviet Union, German Democratic Republic, Bulgaria, Hungary, Afghanistan, Poland, Mongolia, Czechoslovakia, Cuba, Ethiopia, People's Democratic Republic of Yemen, Mozambique, Congo, Grenada, Nicaragua, Jamaica, Guinea, Angola and Seychelles.

(b) Since India's recognition of the Government of the People's Republic of Kampuchea, no other country has so far extended recognition to that Government.

(c) Our recognition of the People's Republic of Kampuchea was based on the realities of the situation in that country; the commitment made by the Government to the people of India, and the national consensus in support of that decision.

Supply of nuclear technology by Switzerland to Pakistan

598. SHRI VILAS MUTTEMWAR: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state the action taken by the Government of India on the news of indirectly passing on nuclear technology to Pakistan by Switzerland and thus helping it in making Atom Bomb?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): The Government has taken note of reports of sale of certain equipment by Swiss firms to Pakistan. Government is taking all possible steps to safeguard India's security.

Government Medical Store Depot., Madras

599. SHRI K.B.S. MANI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Expert Committee appointed by the Government of India to study the Modernisation of the Pharmaceutical Factory attached to the Medical Store Depot, Madras and also the Detailed Project report have submitted its report to Government;

(b) if so, the dates on which these reports were submitted and the action taken by Government thereon;

(c) what are main recommendations of the committee and details of the Project report; and

(d) what is the probable date of completion?